THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Some proposals have been received from time to time to re-start closed textile mills under the cooperative sector. Government is willing to support any concrete, viable proposal for co-operativisation of closed textile mills.

वस्त्र उद्योग में सुधार

2048. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष वस्त्र उद्योग की स्थिति में सुधार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बंद मिलों की संख्या, जोकि अक्तूबर, 1992 में 140 थी, चालू वर्ष में कम होकर 123 रह गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़े का उत्पादन करने वाली इकाइयों को 750 करोड़ रुपये आबंटित किये थे, जिसमें से 710 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों और शेष धनराशि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई थी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1992 में बन्द पड़ी हुई 149 मिलों की तुलना में 22 सूती/मानवनिर्मित फाइबर वस्त्र मिलें समापन की ओर बढ़ ही है(कम्पनी अधिनियम) तथा बंद पड़ी है रतथा 31-5-93 की स्थिति अनुसार विभिन्न कारणों से 100 सूती/मानवनिर्मित फाइबर वस्त्र मिलें अस्थाई रूप से बन्द पड़ी है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वस्त्र मिलों को आधुनिकीकरण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रु० की धनराशि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना स्थापित की है तथा फरवरी, 1993 तक 875.24 करोड़ रु० वितरित कर दिए गए हैं।

क्षेत्रवार वितरण निम्नोक्त अनुसार है :—

निजी	762.29 करोड़ रु०
सरकारी	77.53 करोड़ रु०
सहकारी	35.42 करोड़ रु०

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को 820.14 करोड़ रु० (योजना तथा गैर-योजना) तथा विद्युतकरघा क्षेत्र को 2 करोड़ रु० प्रदान किए थे। तथापि, यह राशि वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना से नहीं दी गई थी।

हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्रों में उत्पादन

2049. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपड़ा उद्योग में बिजलीकरघा क्षेत्र की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में अधिक लोग कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिजली-करघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन देश में कपड़े के कुल उत्पादन का लगभग 72 प्रतिशत होता है जबकि हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन केवल 18 प्रतिशत है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बिजलीकरघा क्षेत्र में उत्पादित कपड़ा हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित कपड़े की तुलना में अधिक सस्ता होता है, यदि हां तो दोनों में कितना अन्तर है ;

(ङ) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजलीकरघा क्षेत्र के विकास के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है चूंकि यह क्षेत्र अधिक और ज्यादा सस्ता कपड़े का उत्पादन करने में सक्षम है ; और

(च) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वस्त्र उद्योग के तीनों क्षेत्रों में नियोजित कामगारों की संख्या निम्नानुसार थी :–

मिल क्षेत्र	10.56 लाख
हथकरघा क्षेत्र	100.00 लाख
विद्युतकरघा क्षेत्र	57.29 लाख

(ग) जी हां।

(घ) विभिन्न किस्मों के कपड़ों की उत्पादन लागत, प्रयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, कपड़े की शुद्धता, श्रम लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं।

(ङ) और (च) सरकार विद्युत-करघा क्षेत्र के अपने सहज बल को मद्देनजर रखते हुए इसके विकास का इरादा रखती हैं। आठवीं योजना अवधि के अन्तिम वर्ष तक इस क्षेत्र द्वारा 18,000 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कपास का निर्यात

2050. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 के दौरान कपास निर्यात करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसार निर्यात की जाने वाली कपास की मात्रा कितनी है और किस महीने के दौरान इसका निर्यात किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार द्वारा कपास के निर्यात का निर्णय लेने से पहले देश में कपास की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कपास के स्थान पर सूत का निर्यात देश के लिये अधिक लाभप्रद है और यदि हां, तो कपास की तुलना में सूत के निर्यात में कितना लाभ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चालू कपास मौसम के दौरान 17.855 लाख गांठें जारी की और इसमें से 27-7-1993 तक 15.175 लाख गांठों की संविदाएं की गई और 11.927 लाख गांठों का लदान किया गया। बकाया मात्रा का लदान अगस्त, 1993 के दौरान किए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी हां। चालू कपास मौसम के दौरान कपास की घरेलू खपत (मिल और गैर-मिल) 120 लाख गांठें आंकी गई हैं।

(घ) जी हां। मई, 93 में भारतीय कपास मिल संघ (आई सी एम एफ) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार